

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)**पीठासीन अधिकारी - गौरव अग्रवाल (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 034/2023 (रा.अ.) (GCMS 2023/305)	दायर दिनांक 20.10.2023	निर्णय दिनांक 19.12.2023
--	---------------------------	-----------------------------

अनवान

आजाद मोहम्मद पिता इमामबक्ष जाति शेख उम्र वयस्क
निवासी सतपुडा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलार्थी**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला
चित्तौड़गढ़।

प्रत्यर्थी

उपस्थिति :- रमेश चन्द्र शर्मा
भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)

अपीलार्थी
प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956
विरुद्ध निर्णय व आदेश न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के प्रकरण
संख्या 482/2021 आदेश दिनांक 29.09.2021**

--: निर्णय :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध प्रत्यर्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश न्याय नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का सपतुडा द्वारा एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए ग्राम सतपुडा की आराजी नम्बर 798 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म बिलानाम पर अवैध अतिक्रमण कर कच्चा मकान निर्माण कर निवास के रूप में काम में लिया जा रहा है। प्रार्थी का उक्त कृत्य दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को नोटिस दिनांक 29.09.2021 को जारी करते हुए मुकाम देवरी पर उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने एवं अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु अवसर चाहा लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर करा घर भेज दिया व उसके बाद उसी दिनांक को बिना किसी साक्ष्य सबुत के प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को मौके से बेदखल करने एवं लगान का 50 गुना शास्ति वसूल करने के आदेश पारित कर दिये जिसके विरुद्ध अपीलार्थी को जानकारी होते ही यह अपील उजर एतराजों के साथ पेश है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने उपस्थित होकर जवाब हेतु अवसर चाहा लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मन मकसुद तरीके से अपीलार्थी को सुनवाई एवं



अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना ही प्रार्थना-पत्र स्वीकारक कर बेदखली व जुर्माने का आदेश पारित कर दिया जो न्याय के नैसृगिक सिद्धांतों के विपरित होने से निरस्त किया जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी सतपुडा की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 14.07.2023 को नोटिस क्रमांक/राजस्व/2023/60 को अपीलार्थी को नोटिस जारी कर सूचित किया कि आप द्वारा ग्राम सतपुडा की आराजी नम्बर 798 किस्म बिलानाम पर कच्चा मकान बना कर अतिक्रमण कर रखा है जिसे 03 दिवस में हटा लेवे अन्यथा प्रशासन द्वारा उक्त अतिक्रमण को दिनांक 21.07.2023 को हटाया जायेगा। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलार्थी सूचित किये बिना ही आनन-फानन में अपीलार्थी को मौके से बेदखल करने का जो आदेश पारित किया है वह विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा ग्राम सतपुडा की आराजी नम्बर 798 रकबा 0.01 हैक्टेयर बिलानाम भूमि पर विगत 100 वर्षों से भी अधिक समय से कच्चा निर्माण कर निवास हेतु उपयोग किया जा रहा है इसके अलावा अन्य भूमि पर अतिक्रमण नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये प्रथम सुनवाई पर ही प्रार्थना-पत्र बिना किसी साक्ष्य सबूत के केवल मात्र पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट को आधार मानते हुए बेदखली व शास्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश पारित किये वह निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के आदेशिका पर उपस्थिति के हस्ताक्षर करा बिना सुनवाई की तारीख की जानकारी दिये बिना ही बाद में पत्रावली में निर्णय पारित कर दिया जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.07.2023 को तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा नोटिस क्रमांक/राजस्व/2023/60 दिनांक 14.07.2023 प्राप्त दिनांक 19.07.2023 को नकल हेतु आवेदन पेश किया जो नकल दिनांक 20.07.2023 प्राप्त हुई और नकल प्राप्त होते ही अपीलार्थी ने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील तैयार करवाई और बिना किसी देरी के न्यायालय में पेश है फिर भी अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षम्य कराये जाने हेतु धारा 05 कानून मियाद का प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र के पेश है। अंत में प्रार्थना की गई कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश दिनांक 29.09.2021 निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

इस पर अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रत्यर्थी की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/राजस्व/2023/165 दिनांक 11.12.2023 से से उनकी मूल पत्रावली संख्या 482/2021 निर्णय दिनांक 29.09.2021 अनवानी सरकार बनाम आजाद मोहम्मद पिता इमामबक्ष निवासी सतपुडा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता है।

दिनांक 12.12.2023 को राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण में सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकरण में उभयपक्ष की सहमति से स्थगन प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही ड्रॉप करते हुए सीधे बहस पत्रावली हेतु रखा गया।



सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना-पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया। अधिवक्ता अपीलार्थी ने मियाद प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के आदेशिका पर उपस्थिति के हस्ताक्षर करा बिना सुनवाई की तारीख की जानकारी दिये बिना ही बाद में पत्रावली में निर्णय पारित कर दिया जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.07.2023 को तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा नोटिस क्रमांक/राजस्व/2023/60 दिनांक 14.07.2023 प्राप्त दिनांक 19.07.2023 को नकल हेतु आवेदन पेश किया जो नकल दिनांक 20.07.2023 प्राप्त हुई और नकल प्राप्त होते ही अपीलार्थी ने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील तैयार करवाई और बिना किसी देरी के न्यायालय में पेश है। इसलिये अपील पेश करने में हुई देरी का क्षम्य किया जाकर अपील को अंदर अवधि दर्ज कर सुनवाई किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया और अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेखों पर दृष्टिपात कराया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया जाकर बाद तामील नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है, अपीलार्थी/अप्रीति को नोटिस का तामील होने से प्रकरण की जानकारी हो चुकी थी, एवं अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.09.2021 को अपीलार्थी स्वयं उपस्थित रहे एवं अतिक्रमण करना स्वीकार किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि पूर्वक निर्णय पारित किया, ऐसी स्थिति में जानकारी होने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई जिस से अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर खारीज फरमाया जावें। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस प्रार्थना-पत्र मियाद अधिनियम समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि अपीलार्थी ने अपीलार्थी का अपील उद्देश्य व्यर्थ हो जायेगा और अपीलार्थी के विरुद्ध बेदखली कार्यवाही होने से भारी परेशानी बढ़ जायेगी जिससे भी अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाना न्यायोचित हैं। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना-पत्र समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना-पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना-पत्र का मनन किया। प्रकरण में मियाद के साथ-साथ गुणावगुण पर भी देखा जाना उचित प्रतीत होता है, अतः प्रार्थना-पत्र के निर्णय को रिवर्ज करते हुये पत्रावली को गुणावगुण पर सुनने के आदेश दिये गये।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश न्याय नियम एवं वाक्याती तथ्यों के विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का सप्तपुडा द्वारा एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए ग्राम सप्तपुडा की आराजी नम्बर 798 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म बिलानाम पर अवैध अतिक्रमण कर कच्चा मकान निर्माण कर निवास के रूप में काम में लिया जा रहा है। प्रार्थी का उक्त कृत्य दण्डनीय



अपराध की श्रेणी में आता है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को नोटिस दिनांक 29.09.2021 को जारी करते हुए मुकाम देवरी पर उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने एवं अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु अवसर चाहा लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर करा घर भेज दिया व उसके बाद उसी दिनांक को बिना किसी साक्ष्य सबूत के प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को मौके से बेदखल करने एवं लगान का 50 गुना शास्ति वसूल करने के आदेश पारित कर दिये जिसके विरुद्ध अपीलार्थी को जानकारी होते ही यह अपील उजर एतराजों के साथ पेश है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने उपस्थित होकर जवाब हेतु अवसर चाहा लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मन मकसुद तरीके से अपीलार्थी को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना ही प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर बेदखली व जुर्माने का आदेश पारित कर दिया जो न्याय के नैसृगिक सिद्धांतों के विपरित होने से निरस्त किया जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी सतपुडा की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 14.07.2023 को नोटिस क्रमांक/राजस्व/2023/60 को अपीलार्थी को नोटिस जारी कर सूचित किया कि आप द्वारा ग्राम सतपुडा की आराजी नम्बर 798 किस्म बिलानाम पर कच्चा मकान बना कर अतिक्रमण कर रखा है जिसे 03 दिवस में हटा लेवे अन्यथा प्रशासन द्वारा उक्त अतिक्रमण को दिनांक 21.07.2023 को हटाया जायेगा। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलार्थी सूचित किये बिना ही आनन-फानन में अपीलार्थी को मौके से बेदखल करने का जो आदेश पारित किया है वह विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

इसके जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली में बताया कि विवादित आराजीयात राजकीय भूमि दर्ज अभिलिखित है एवं अपीलांट का कब्जा राजकीय भूमि पर होने से नियमन की पात्रता नहीं रखता है, जिससे अपीलांट की अपील सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। प्रचलित नियमों के अनुसार राजकीय भूमि आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये, ऐसी स्थिति में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। अतः तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है, एवं प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का निवेदन की ईशतदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम सतपुडा की आराजी नम्बर 798 रकबा 0.01 हैक्टेयर बिलानाम भूमि पर विगत 100 वर्षों से भी अधिक समय से कच्चा निर्माण कर निवास हेतु उपयोग किया जा रहा है इसके अलावा अन्य भूमि पर अतिक्रमण नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये प्रथम सुनवाई पर ही प्रार्थना-पत्र बिना किसी साक्ष्य सबूत के केवल मात्र पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट को आधार मानते हुए बेदखली व शास्ति अधिरोपित किये जाने के आदेश पारित किये वह निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित



निर्णय व आदेश दिनांक 29.09.2021 निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। इसी ईशुदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का बागौर अवलोकन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। हमने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिनियम में धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि :-

91 Unauthorised occupation of Land - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful authority shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted therefrom by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and any crop standing, or any building or other construction erected, or anything deposited on such land shall, if not removed within such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases as the Collector may direct:

Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.

(2) Such trespasser shall further be liable to pay, for each agricultural year during the whole or any part whereof has been in such unauthorized occupation of the land, a penalty which may extend to fifty times the annual rent, or assessment, as the case may be, for the first act of trespass. In the case of each subsequent act of trespass, he shall by the order of Tehsildar, be liable to commitment to civil prison for a term which may extend to three months and to pay penalty to the extent as aforesaid. The amount of such penalty shall be recovered as an arrear of land revenue, and]

(3) Where the trespasser ordered to be committed to civil prison under subsection (2) satisfies the Tehsildar by whom he is ordered to be committed to civil prison that he intends to present an appeal, the Tehsildar shall order that such trespasser be released on his own bond for such periods will afford him sufficient time to present the appeal and obtain stay order from the Appellate Court and such order shall so long as he is so released on bond be deemed to be suspended]

(4) In any of the following cases, namely:-

(i) where the trespasser does neither vacate the land nor make appearance in response to the notice issued under sub-section (3), or

(ii) where in response to such notice, the trespasser does not vacate the land and makes appearance but-

(a) does not show any such cause, or

(b) makes any representation which is rejected after such inquiry and hearing as may be necessary in the circumstances of the case, the Tehsildar shall, unless, in the case covered by clause (ii) the trespasser undertakes to vacate the land within a week's time and vacates it within such time order the removal of the trespasser from such land and shall remove or depute any person, to remove him therefrom and take possession thereof; and if the Tehsildar or the person so deputed is opposed or impeded in taking possession of such land, the Tehsildar shall apply to a Magistrate having jurisdiction and such Magistrate shall enforce the surrender of the land to the Tehsildar.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Tehsildar may, in case any such land belongs to the category specified in clause (ii) of the proviso to Section 97, sell it, with the approval of the Sub-Divisional Officer, to the trespasser upon payment by him of the premium therefor at the rate fixed under Section 96 and applicable to such land in addition to the assessment and penalty recoverable from him under sub-section (2) in respect of the whole period of unlawful occupation

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) - (a) whoever occupies any land without lawful authority or, having occupied such land before coming into force of the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 1992, fails to remove such occupation within



fifteen days from the date of service of a notice in writing calling upon him to do so by the Tehsildar shall, on conviction, be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to three years and with fine which may extend to twenty thousand rupees; and

(b) whoever, being an employee of the State Government specifically entrusted by an order of the Collector in writing with the duty to stop or prevent an offence punishable under this sub-section wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop or prevent such offence, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both :

Provided that, in the case of an offence under clause (a), the court may for any adequate or special reason to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than one month :

Provided also that no investigation of an offence under clause (a) of this sub section shall be made by an officer below the rank of a Deputy Superintendent of Police :

Provided further that no court shall take cognizance of an offence under clause (b) except with the previous sanction of the Collector.

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/ परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। भूमि चरागाह दर्ज होने से पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करके बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया। चरागाह भूमि गांव के मवेशी चराने की भूमि होती है, इस पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान में चरागाह दर्ज रिकार्ड है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किया गया एवं अपीलार्थी द्वारा आराजीयात जैरबहस पर अपना अतिक्रमण होना अपील में अंकित किया गया है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है। इसके साथ अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य को भी उठाया गया है कि अपीलार्थी का आराजीयात जैरबहस पर कब्जा नहीं है, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर आता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा स्वयं कब्जा होना स्वीकार किया गया है, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध परचा मौका दिनांक 15.09.2021 मौतबिरान की उपस्थिति में हल्का पटवारी द्वारा तैयार किया गया है, जिससे पुष्टि होती है कि अपीलार्थी द्वारा आराजीयात जैरबहस पर अतिक्रमण किया गया है, एवं प्रश्नगत आराजीयात पर अपीलार्थी का किसी भी प्रकार से हक हिस्सा निहित नहीं होना प्रमाणित पाया जाता है। इसके साथ ही वर्तमान परिस्थितियों में प्रश्नगत आराजीयात चरागाह दर्ज रिकार्ड है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किया गया है, विवादित आराजीयात चरागाह दर्ज रेकार्ड है एवं चरागाह पर किसी भी प्रकार से अतिक्रमण को प्रोत्साहन दिया जाना उचित नहीं है। हमने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राप्त अभिलेख का बागौर अवलोकन, परिशीलन/परीक्षण किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.09.2021 का अवलोकन किया। अपीलार्थी/अप्रार्थीगण को जारी नोटिस का गहनता पूर्वक अवलोकन किया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर नियमानुसार निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.09.2021 विधि सम्मत होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन एवं हस्तक्षेप की



आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.09.2021 संपुष्ट किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

हस्तगत प्रकरण में मियाद प्रार्थना-पत्र पर निर्णय पारित किया जाना शेष है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपील में के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.09.2021 अपीलार्थी की उपस्थिति में पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के फर्द अहकाम से प्रमाणित पाई जाती है। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा अपने मियाद प्रार्थना-पत्र में अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी को निर्णय दिनांक 29.09.2021 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.07.2023 को प्राप्त हुई जिसके पश्चात् अपीलार्थी द्वारा नकल आवेदन प्रस्तुत किया गया। अपील में के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से जाहिर आता है अपीलार्थी को उक्त प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 20.07.2023 को प्राप्त होने के उपरांत भी अपील अपीलार्थी इस न्यायालय में दिनांक 04.09.2023 को प्रस्तुत हुई है जो कि लगभग 44 दिनों विलम्ब से प्रस्तुत हुई है एवं इसके तथ्य के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई भी संतोषप्रद तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी प्रस्तुती में विलम्ब को क्षम्य किये जाने का कोई ठोस आधार अपीलार्थी पत्रावली पर प्रस्तुत करने में पूर्णतया असफल रहे जिससे अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर पोषणीय नहीं पाई जाती है। इसके साथ ही उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलार्थी गुणावगुण पर भी खारीज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व अपील प्रकरण संख्या 034/2023(रा.अ.) अनवानी आजाद मोहम्मद बनाम सरकार अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर एवं गुणावगुण (दोनों) पर बलहीन होकर सारहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय प्रकरण संख्या 482/2021 निर्णय दिनांक 29.09.2021 अनवानी सरकार बनाम आजाद को यथावत रखा जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 29.09.2021 की पुष्टि की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 19.12.2023 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़